है, वे उसका सामना कर सकें, इसके लिए हम ऐसे बीजों के संशोधन में लगे हुए हैं। बेसिकली, श्री संभाजी छत्रपती साहब का जो सवाल था, वह इन्होंने यंत्रीकरण के ऊपर ही रखा था। यंत्रीकरण भी yield डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा तरीका है। यंत्रीकरण के उपमिशन के द्वारा हमने 49,000 किसानों को ट्रेनिंग दी है और किसानों के लिए हमने एक नया concept custom hiring center लागू करवाया है। जहाँ किसान खुद नहीं खरीद सकता - जैसे ओला-ऊबर का प्रयोग हम ट्रेवलिंग के लिए कर सकते हैं, ऐसे ही ऐप के माध्यम से अब किसानों को अपने फार्म के लिए ट्रेक्टर भी मिलें, इस प्रकार की सुविधा का प्रयोग हम कर रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 204.

Implementation of NFSA

*204. LT. GEN. (DR.) D.P. VATS (RETD.): Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the norms and procedures followed to identify the beneficiaries under National Food Security Act (NFSA);

(b) the action plan formulated by Government to ensure proper and impartial implementation of NFSA; and

(c) whether any improvement in the standard of nutrition of the poor people, particularly children and women, have been noticed after the implementation of the Act, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DANVE RAOSAHEB DADARAO): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) NFSA legally entitles upto 75% of the rural population and 50% of the urban population to receive highly subsidized foodgrains under the Targeted Public Distribution System (TPDS). The percentage coverage under the TPDS in rural and urban areas for each State was to be determined by the Central Government and the total number of persons to be covered in such rural and urban areas of the State was to be calculated on the basis of the population estimates as per the latest census of which the relevant figures had been published. Coverage under the Act is under two categories *viz.* Antyodaya Anna Yojana (AAY) households and priority households (PHH). As per provisions of the Act, within the state/UT-wise coverage, State Governments/UT

Administrations are required to identify the households to be covered under the AAY in accordance with the guidelines applicable to the said scheme and the remaining households as priority households, in accordance with such guidelines as the State Governments may specify. Each of the States/UTs have evolved their own guidelines for this purpose based on different exclusion/inclusion criterion.

(b) The Action Plan to ensure proper and impartial implementation of the National Food Security Act aims to strengthen and streamline the operation of the Targeted Public Distribution System (TPDS). Government in collaboration with States/UTs is implementing End-to-End Computerization of PDS Operations' which comprises digitization of ration cards/beneficiaries data and de-duplication, computerization of supply chain management of foodgrains, setting up of transparency portal and online grievance redressal mechanisms in all States/UTs. Till November 2019,4.45 lakh FPSs out of total 5.35 lakh FPSs in the country had ePoS devices. About 85.8% of the total ration cards in the country have currently been seeded with Aadhar number to ensure transparency and rightful targeting of food subsidy. Delivery of foodgrains upto door-steps of fair price shops is also being ensured to prevent diversion and leakages of foodgrains under TPDS.

(c) No study has been conducted to directly assess the improvement in the standard of nutrition of women and children after the implementation of the National Food Security Act (NFSA) 2013. However, findings of some Surveys made are as follows:

(i) The only available National level dataset providing nutritional data for women and children is the National Family Flealth Survey (NFHS). Comparison of NFHS 3 (2004-05) with NFHS 4 (2015-16), shows about 55.1 percent of children less than six years received supplementary nutrition under NFHS 4 as compared to 29.9 percent children during NFHS 3.

(ii) Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW), Government of India with support from UNICEF has conducted the first ever Comprehensive National Nutrition Survey (CNNS), during 2016 to 2018 in 30 States. The CNNS results highlight improvements by reduction in stunting (height for age), wasting (weight for height) and underweight (weight for age) in children below five years of age from 38.4% to 34.7%, 21.0% to 17.3% and 35.7% to 33.4% respectively as compared to NFHS-4 (2015-16).

LT. GEN. (DR.) D. V. VATS (Retd.): Sir, the Government has taken a very ambitious plan to cover 75 per cent of rural population and 50 per cent of urban population under Public Distribution System. I would like to know from the hon. Minister, through you, what is the extent of fake, duplicate ration cards issued to the people. There are reports that even illegal immigrants also got fake ration cards. What is the Government doing to eradicate this evil?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: उपसभापति महोदय, सरकार की ओर से जाली राशन कार्ड को रोकने के लिए राशन की दुकानों में POS मशीनें लगाई गई हैं। उस मशीन के द्वारा राशन उसी व्यक्ति को जाता है, जिसके पास सही राशन कार्ड होता है। उसके अलावा जो राशन कार्ड थे, वे जाली राशन कार्ड्स सरकार द्वारा रद्द कर दिए गए। महोदय, उनकी पहचान केवल POS मशीनों के ज़रिए ही हो सकती है।

माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है, उसके मापदंड क्या हैं? महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि 5 जुलाई, 2013 को जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ, वह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। इसमें जो मापदंड रखे गए, उनके अनुसार 75 प्रतिशत ग्रामीण एवं 50 प्रतिशत शहरी लोगों को इसमें कवर किया गया है। इस देश में 81.35 करोड़ आबादी इसमें लक्षित की गई, जिसमें से 79 करोड़ लोगों को आज हम इसके माध्यम से अनाज दे रहे हैं। इसके जो मापदंड हैं, उसके आधार पर ज्यादातर राज्य सरकार ही इसकी पहचान करती है। यह राज्य सरकार की तरफ से ही किया जाता है।

श्री उपसभापति: दूसरा सप्लिमेंटरी।

LT. GEN. (DR.) D.P. VATS (RETD.): What is the status of the one nation-one-ration-card policy proposed to end leakages in the public distribution system?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: उपसभापति महोदय, हमारा "वन नेशन, वन राशन कार्ड" अभी ट्रायल बेसिस पर चल रहा है और उसके लिए हमने क्लस्टर्स बनाए हैं। जैसे, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में इसके क्लस्टर्स बनाए गए हैं। आज छ: राज्यों में ये क्लस्टर्स बने हैं और आने वाले दिनों में इसके और छ: क्लस्टर्स बनने के बाद 12 राज्यों का एक क्लस्टर पूरा हो जाएगा और इस तरह से यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

श्री राकेश सिन्हा: उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस सवाल के लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूँ।

श्री उपसभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री राकेश सिन्हा: सर, मेरा सवाल यह है कि जो पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है, उसमें

[श्री राकेश सिन्हा]

जिन लोगों के पास डिस्ट्रिब्यूशन की जिम्मेदारी होती है, उसमें एक ही व्यक्ति कई बार रिपीट होता है। उसका सबसे बड़ा असर यह होता है कि समाज का जो marginalized section है, उसका जो due है, वह उसे नहीं मिल पाता है।

श्री उपसभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री राकेश सिन्हा: मैं पूछना चाहता हूँ कि एक ही व्यक्ति के पास इसके डिस्ट्रिब्यूशन की जिम्मेदारी लगातार न रहे, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? इस cyclical काम को करने के लिए क्या सरकार नियम में कोई परिवर्तन करेगी?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: उपसभापति महोदय, इसकी जो व्यवस्था है, वह राज्य सरकार के पास है। इसका डिस्ट्रिब्यूशन राज्य सरकार करती है। इस देश में 85.81 परसेंट कार्ड्स "आधार" से जोड़े गए हैं। खाद्यान्नों की leakage रोकने के लिए भी हम उनके द्वार तक खाद्यान्न पहुँचाते हैं। मुझे लगता है कि यह व्यवस्था पूरी तरह से राज्य सरकारें देखती हैं।

SHRI RIPUN BORA: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether under the Food Security Act there is a mechanism with the Government o periodically review the condition of the card holders, because after getting the cards they come above thee poverty line and become rich during the pendency of the card. क्या आपने उन लोगों के कार्ड्स कैंसिल करने के लिए कोई व्यवस्था की है?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: उपसभापति महोदय, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है कि इससे 79 परसेंट आबादी को कवर किया गया है और 81.35 परसेंट आबादी को इससे कवर करना है। यह जो fluctuation है, यह इसी में आ जाता है। जब कोई आदमी नहीं रहता है या किसी कारण से वह स्थानान्तरित हो जाता है, तो उसके लिए भी हमने अभी एक कार्ययोजना तैयार की है।

श्रीमती जया बच्चन: सर, हमारे पास जो लिखित जवाब आया है, उसमें TPDS, AAY, PHH आदि लिखा गया है। By the time you realize what it means, to understand it is a big problem. मेरी रिक्वेस्ट यह है कि आप अपने कर्मचारियों से कहिए कि वे इसको थोड़ा विस्तार करके लिखें।

श्री उपसभापति: मंत्री जी, यह सुझाव है, आप इस पर ग़ौर कर लें।

श्रीमती जया बच्चन: महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूं कि from the point of purchase of foodgrains till its distribution, what kind of transparent mechanism have you planned?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: उपसभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न पूछा है, यह बात सही है कि इसमें फॉर्म दिया है। AAY का मतलब होता है, 'अंत्योदय अन्न योजना'।